अनुदान संख्या 83 - उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
GRANT No. 83 - SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	11,30,00			
			12,68,00	10,68,95	-1,99,05
पूरक	Supplementary	1,38,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,99,06
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		31,00	29,38	-1,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1,62

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹199.05 लाख) दिसंबर, 2024 में प्राप्त किए गए ₹138.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं। अभ्यर्पित राशि (₹199.06 लाख) भी कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः –

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹199.05 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹138.00 lakhs obtained in December, 2024 and constituted 16 percent of the total sanctioned provision. The amount surrendered (₹199.06 lakhs) also exceeded the overall savings.

Savings occurred under the following major head: -

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2012"	Major Head "2012"				
राष्ट्रपति, उप–राष्ट्रपति, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल / प्रशासक	President, Vice President, Governor/ Administrator of Union Territories				
मू.	O.	1130.00			
पू.	S.	138.00	1068.94	1068.95	+0.01
पु.	R.	-199.06			

(I) "उप–राष्ट्रपति – सचिवालय – स्थापना" के अंतर्गत ₹1122.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹138.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1260.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹198.17 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Under "Vice President - Secretariat - Establishment" - the original provision of ₹1122.00 lakhs was augmented to ₹1260.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹138.00 lakhs. However, there was a saving of ₹198.17 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.